

13/12/23 पत्रावली पेशा। वकील वाडी डपॉ
वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3 डपॉ।
प्रा. पत्र 07R/11 CPC संपठित धारा 15
CPC पर दौनी अधिवक्तागण की बहस
शुनी गरी वारंते आपदेश हेतु पत्रावली
दिनांक 15/12/2023 को पेश हो।

15/12/23 पत्रावली पेशा। पत्रावली का भवलाकन
किया गया। उन्नयपक्ष बहस पर मनन
Punjab

Date

Order with initials of Presiding Officer

Brief

क्रिया गया प्रतिवादी सं. 02, 03 की ओर से प्रा. पत्र संतर्गत 07 R॥ पेश किया गया। मुताबिक बहस अचि. प्रतिवादी सं. 02, 03 - "वादी वादग्रस्त भूमि का सातेदार नहीं है, अतः वह रियाई निषेधाज्ञा का वाद लाने हेतु हकदार नहीं है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में जो. वि. प्रा. की सातेदारी में दर्जसुदा है और इस भूमि का राज. भू- राजस्व अचि. 195 की धारा 90(क) के तहत गैर- कृषिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण दिनांक 31.08.2022 को हो गया है। अतः राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के आवासीय पट्टे जारी किये जा चुके हैं। अतः पट्टाधारकों को भी पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाने। वादी द्वारा अपने हक में क्लेम की गई भूमि राज्य सरकार द्वारा आम सड़क प्रयोजनार्थ अचिग्रहीत कर ली गई थी और इसका मुआवजा भी वादी को जरिए बैंक भ्रदा कर दिया गया था, अतः वाद वादी श्वारिज फेरमाया जावे।"

मुताबिक बहस अचि. वादी -

"प्रति सं. 01 ने वादी को वादग्रस्त भूखंड का बेचान जरिए पंजीबद्ध बंधनामा किया। उक्त भूखंड का नाप फुट व वर्ग गज में होने के कारण पटवारी ने नामांतरण दर्ज नहीं किया। दौरान भू-रूपांतरण कार्यवाही वादी ने जो. वि. प्रा. में आपत्ति दर्ज करवाई। प्रति. सं. 02 व 03 ने सिविल न्यायालय में एक प्रा. पत्र संतर्गत 07 R॥ पेश किया, जिसका निस्तारण करते हुए सिविल न्यायालय ने उक्त भूमि को कृषि भूमि माना। जिस समय वाद हेतुक अपना हुआ, उक्त भूमि की प्रकृति कृषि थी। अतः राजस्व न्यायालय को वाद श्वरण का क्षेत्राधिकार

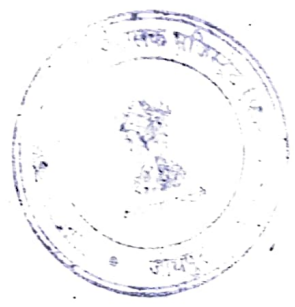
Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
------	--	---------------------------------------

प्राप्त है। वादी की भूमि आम सड़क हेतु अचिग्रहीत नहीं की गई है और ना ही वादी ने इस हेतु किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त किया है। वादी द्वारा प्रति. सं. 01 से खरीदमुदा कृषि भूमि, प्रति. सं. 01 ने पुनः प्रति. सं. 02 व 03 को बेचान कर दी, जिसके बाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रा-पत्र खारिज फरमाया जावे।"

आदेश

उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आचार पर प्रति सं. 02 व 03 की और से 07 R.11 के तहत दारिजल प्रा-पत्र का विस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-
 "As per section 188 of Rajasthan Tenancy Act - Any tenant whose right to whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded may bring a suit for grant of perpetual injunction".
 According to this section, application under 07 R.11, CPC is being accepted & suit is dismissed as Plaintiff is not a tenant of disputed land nor he has filed any case for declaration of right". पत्रावली में आदेश पढ़कर खुले में सुनाया गया। पत्रावली फंसल नुमार होकर दारिजल दफतर हो

Printed



मजिस्ट्रेट का दफतर
 मजिस्ट्रेट का दफतर
 मजिस्ट्रेट का दफतर